



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १६(२)]

सोमवार, जून २२, २०१५/आषाढ १, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

राजस्व तथा वन विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित १२ जून २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2015.

**AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE
CODE, 1966.**

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२, सन् २०१५।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके
सन् १९६६ कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन
का महा. करने के लिये सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;
४१।

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९६६ का
महा. ४१ ।
सन् १९६६ का
महा ४१ की धारा
४८ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे “ राजस्व संहिता ” कहा गया है) की धारा ४८ की,—

(एक) उप-धारा (७) में,—

(क) “ कलक्टर के लिखित में आदेश पर, तीन गुना से निर्धारित किसी राशि से अधिक न होनेवाली शास्ति अदा करने ” शब्दों के स्थान में “ कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी के लिखित में आदेश पर पाँच गुना से समतुल्य शास्ति अदा करने ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) परंतुक, निरसित किया जायेगा ।

(दो) उप-धारा (८) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

“(८)(१) उप-धारा (७) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर या कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत तहसिलदार से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा जिसमें अधिकार विहित और समनुदेशित नहीं है, वहाँ उप-धारा (७) में निर्दिष्ट किसी खान, या खदान या अन्य जगह से निष्कर्षण किये गए, हटाये गये, संग्रहित, पुनःस्थापित या उठाये गए या निपटान किये गये किन्हीं खनिजों का अभिग्रहण और अधिहरण कर सकेगा और गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण करने, हटाने, संग्रहण, पुनःस्थापना, उठाये जाने या निपटान और उसके समान परिवहन के लिये अभिनियोजित परिवहन की किसी यान्त्रिकी साधन के उपयोग के लिये किसी मशीनरी और उपकरण का भी अभिग्रहण और अधिहरण कर सकेगा ।

२. उप-धारा (१) के अधीन अभिग्रहित गौण खनिजों के अनधिकृत उद्भरण, हटाने, संग्रहण, पुनःस्थापन, चुने जाने या निपटान के लिए उपयोगी परिवहन की ऐसी मशीनरी या उपकरण या साधन और गौण खनिजों का परिवहन इस निमित्त कलक्टर या कलक्टर द्वारा प्राधिकृत उप कलक्टर से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण के अडतालीस घंटों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जाएँगे, ऐसा अधिकारी जो जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शास्ति उसके स्वामी द्वारा अदायगी करने पर, परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन ऐसे अभिग्रहित है तो रिहा कर सकेगा, को प्रस्तुत करेगा और उसमें परिवहन के अभिग्रहित मशीनरी, उपकरण या कथन किये गए साधन के बाजारमूल्य से अनधिक ऐसी रकम का स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत करता है कि, ऐसे अभिग्रहित परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन का उपयोग भविष्य में गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण, हटाने, संग्रहण पुनःस्थापन, उठाये गये या निपटान करने के लिए नहीं किया जायेगा ।

सन् १९६६ का
महा ४१ की धारा
३२८ में संशोधन ।

३. राजस्व संहिता की धारा ३२८ की, उप-धारा (२) में, खंड (उन्नीस) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(उन्नीस) धारा ४८ की उप-धारा (८) के अधीन गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण, हटाने, संग्रहण, पुनःस्थापन, उठाये जाने या निपटान के लिये उपयोगी परिवहन की मशीनरी, उपकरण या साधन को रिहा करने के लिये स्वामी द्वारा अदा की जानेवाली शास्ति के विहित नियमों और धारा ४८ की उप-धारा (९) के अधीन गौण खनिजों के उद्भरण और हटाने के नियमों को विनियमित करना ; ”।

वक्तव्य

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) की धारा ४८ खान और खनिजों को सरकारी हकों के लिये उपबंध करती है।

उक्त धारा ४८ की उप-धारा (७), विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, निष्कर्षण हटाये गये, संग्रहित, प्रतिस्थापित, उठाये गए या निपटान किये गये खनिजों के बाजार मूल्य तीन गुना अभिनिर्धारित की गई रकम से अनाधिक शास्ति के लिये उपबंध करती है। महाराष्ट्र सरकार, इस प्रकार निष्कर्षण, हटाये गये, संग्रहित, प्रतिस्थापित, चुने जाने या निपटान किये गये खनिजों के बाजार मूल्य के “तीन गुना” से “पाँच गुना” तक शास्ति बढ़ाने के लिये उप-धारा (७) संशोधित करना, ईष्टकर समझती है।

उक्त धारा ४८ की उप-धारा (८), यह उपबंध करती है कि, कलक्टर राज्य सरकार द्वारा, जिसमें अधिकार निहित और समनुदेशित नहीं है वहाँ उप-धारा (७) में निर्दिष्ट किसी खान, खदान या अन्य जगह से उद्धरित, हटाये गये, संग्रहित, प्रतिस्थापित, उठाये गए या निपटान किये गये किन्हीं खनिजों का अभिग्रहण और अधिहरण कर सकेगा। तथापि, उप-धारा (८) के उपबंध, कलक्टर को, गौण खनिजों के अनधिकृत उद्धरण, आदि के लिये उपयोग की गई मशीनरी और साधन उपकरणों और ऐसे गौण खनिजों के परिवहन के लिये अभिनियोजित परिवहन साधनों के अभिग्रहण और अधिहरण के लिये सशक्त नहीं करती है।

इसलिये, गौण खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन की रोकथाम की दृष्टि से, कलक्टर या कलक्टर द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत उप-कलक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को, गौण खनिजों के अनधिकृत निष्कर्षण, आदि के लिये उपयोग की गई मशीनरी और उपस्कर और ऐसे गौण खनिजों के परिवहन के लिये उपयोग किये गये परिवहन साधनों के अभिग्रहण और अधिहरण के लिये, उक्त धारा ४८ की उप-धारा (८) के प्रतिस्थापन द्वारा शीघ्रतम प्रभाव के साथ सशक्त करना ईष्टकर समझा गया है।

२. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १२ जून २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनु कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।